फरीदाबाद
मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 221 · नवम्बर 2006

प्रगति–विकास

फोन, कम्प्युटर, उपग्रह, इन्टरनेट, कैमरे सेना, पुलिस और खुफिया विभागों की विश्व में हर स्थान पर हर समय जकड़ बढा रहे हैं। छोटे-से इंग्लैण्ड में लोगों पर चौबीसों घण्टे नजर रखने के लिये चालीस लाख कैमरे लगे हैं......

मजदूरों को दिखाना ही नहीं (5)

गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

✱ कानूनी और गैर-कानूनी में चोली-दामन का साथ रहा है। प्रहरी, कोतवाल, मन्त्री द्वारा रिश्वत लेने के किस्से बहुत पुराने हैं। दरअसल दमन-तन्त्र रिश्वत की चर्बी के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिये नगर-प्रान्त-देश के दायरों में कैद हो कर भ्रष्टाचार आदि को मूल समस्या मानना नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, गैर-कानूनी को मर्ज और कानून को दवा पेश कर कानून अनुसार दमन-शोषण को छिपाने का नुस्खा पुराना है, यह शुद्ध काँइयापन है। ✱ आज नई बात दमन-तन्त्र के संग-संग शोषण-तन्त्र में भी कानूनों का उल्लंघन, गैर-कानूनी कार्यो का बहुत-ही बड़े पैमाने पर होने लगना है। मण्डी-मुद्रा के साम्राज्य में कानूनों का यह अर्थहीन होना राजाओं-सामन्तों के अन्तिम चरण में कानूनों के अर्थहीन होने जैसा लगता है। दिल्ली और इसे घेरे नोएडा, सोनीपत, बहादुरगढ, गुड़गाँव, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में कार्य करते 70-75 प्रतिशत मज़दूरों को अब दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं को विलाप की वस्तु की बजाय नई सम्भावनाओं से ओत-प्रोत के तौर पर देखना बनता है।

मण्डी-मुद्रा की गतिक्रिया के चलते, मण्डी-मुद्रा के दबदबे के चलते कानूनी/गैर-कानूनी में हुई इस उलट-फेर की अनिवार्यता के सन्दर्भ में यहाँ हम इन दो सौ वर्षों के दौरान मालिकाने में आये परिवर्तनों पर चर्चा जारी रखेंगे।

● बँटे हुये समाज में, ऊँच-नीच वाले समाज में जिस चीज के निर्माण में ज्यादा समय लगता है, बनाने में लागत अधिक आती है, संचालन भारी खर्च माँगता है उस चीज के लिये संस्था-इन्सटिट्युशन-कम्पनी होना एक अनिवार्यता हो जाती है। किलों के लिये सरकार जरूरी थी। दूरदराज से व्यापार के वास्ते संस्था-कम्पनी जरूरी थी। उन्नीसवीं सदी में जब रेल यातायात की बात उठी तो रेल कम्पनियाँ एक अनिवार्यता बनी। आज जैसे फैक्ट्रियाँ कम्पनियों की हैं और उनके निदेशक मण्डल तथा चेयरमैन व डायरेक्टर हैं वैसे ही रेलवे में आरम्भ से कम्पनियाँ और उनके निदेशक मण्डल, अध्यक्ष, निदेशक हैं अथवा वे सरकार के हैं।

● यूरोप में 1850 के आसपास फैक्ट्री इस या उस व्यक्ति की होना व्यापक था परन्तु फैक्ट्री स्थापना-संचालन की बढती लागत फैक्ट्री में एक आना-चार आना-छह आना की हिस्सेदारियों को उभारने लगी थी। लागत तेजी से बढी और 1895 के आसपास फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी व्यापक बनी। शोषण में हिस्सेदार लोग आपस में हेराफेरी करने में कोई कंजूसी नहीं बरतते।

● कर से बचने के प्रयास हजारों वर्ष पूर्व सरकारें बनने के दौर में ही आरम्भ हो गये थे और आम बात रहे हैं। फैक्ट्री मालिक द्वारा टैक्स चोरी भी सामान्य थी। फैक्ट्री का कोई एक मालिक होने की बजाय फैक्ट्री में हिस्सेदार होने लगे तब सामान्य टैक्स चोरी में कुछ और बातें भी जुड़ गई। हिस्सेदार लोग एक-दूसरे से हेराफेरी के लिये फैक्ट्री की मालिक अपनी ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी से भी चोरी करने लगे। जब तक एक व्यक्ति फैक्ट्री का मालिक था-थी तब तक ऐसी चोरी के लिये स्थान नहीं था। लेकिन "मालिक नहीं, पर फिर भी मालिक" वाली नई स्थिति ने नई चोरी को जन्म दिया। काँइयापन में अव्वल हिस्सेदार लोग एक-दूसरे पर तीखी नजरें रखते थे इसलिये सौ वर्ष पूर्व की एक आना-चार आना हिस्सेदारी वाली ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियों में कम्पनी की अधिक चोरी नहीं हो पाती थी क्योंकि इस चोरी का एक अर्थ हिस्सेदारों की चोरी भी था।

● फैक्ट्री की स्थापना-संचालन की लागत में बढोतरी जारी रही। लागत में बढोतरी रफ्तार पकड़ती आई है। पिछली सदी के आरम्भ से फैक्ट्री मालिक भूत बने, फैक्ट्री के दस-बीस हिस्सेदार वाली स्थिति भी तेजी से विगत की वस्तु बनी। फैक्ट्री की स्थापना-संचालन की लागत 1900 आते-आते इतनी बढ गई थी कि दस-बीस द्वारा मिल कर यह करना भी अधिकाधिक कठिन होता जा रहा था। फैक्ट्री की स्थापना-संचालन के लिये हजारों शेयरहोल्डरों से धन एकत्र करना एक अनिवार्यता के तौर पर उभरा। लेकिन आज सौ-सवा सौ वर्ष बाद भी "फैक्ट्री मालिक" का भूत बहुत गड़बड़ कर रहा है और यहाँ इस चर्चा का एक कारण बना है।

● फैक्ट्री का आकार तथा लागत बढना मालिक की जगह पहले दस-बीस हिस्सेदार लाया और फिर हजारों शेयरहोल्डर। कुछ लोगों की हिस्सेदारी वाली ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी की जगह हजारों शेयरहोल्डरों वाली कम्पनी फैक्ट्री के मालिकाने में बड़ा परिवर्तन लाई। हिस्सेदार जहाँ एक-दूसरे को और फैक्ट्री को जानते थे वहाँ दूर-दूर फैले शेयरहोल्डर न तो एक-दूसरे को जानते थे और न ही उनमें से अधिकतर ने कभी वह फैक्ट्री देखी जिसके वे शेयरहोल्डर होते थे-हैं। जिक्र कर दें कि पिछली सदी के आरम्भ में जमशेदपुर में स्थापित होने वाली टाटा आयरन एण्ड स्टील फैक्ट्री की कम्पनी के शेयर लन्दन स्टॉक मार्केट पर बेचे गये थे। हजारों शेयरहोल्डरों वाली फैक्ट्री के संचालन के लिये बने निदेशक मण्डल के सदस्यों के पास शेयरों का एक छोटा-सा प्रतिशत ही होता था। अध्यक्ष और अन्य डायरेक्टरों पर शेयरहोल्डरों की प्रत्यक्ष लगाम वार्षिक लाभ वितरण पर समर्थन-विरोध में सिमट गई। और, सामान्यतः अधिकतर शेयरहोल्डरों के लिये इस वार्षिक अनुष्ठान में प्रत्यक्ष शिरकत लाभदायक नहीं थी। शेयरहोल्डरों द्वारा अपना मताधिकार अन्य को सौंपने की परिपाटी बनी। सट्टा बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री एक बड़ा धन्धा बना।

● चन्द हिस्सेदारों की जगह हजारों शेयरहोल्डर, संचालक निदेशक मण्डल के सदस्यों की थोड़ी-सी राशि लगे होने, चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य डायरेक्टरों पर नियन्त्रण बहुत ढीला होने, पैसा शक्ति-सत्ता-सम्पन्नता की कुँजी होने के दृष्टिगत डायरेक्टरों द्वारा कम्पनी की चोरी सामान्य बनी। "मालिक नहीं, पर फिर भी मालिक" वाले व्यवहार ने नये चरण में प्रवेश किया। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदचिन्हों पर जनरल मैनेजर चले। जनरल मैनेजरों का अनुसरण स्टॉफ के अन्य लोगों ने किया। शेयरों के स्थान पर कर्ज के मुख्य भूमिका में पहुँचने ने क्या गुल खिलाये इसकी चर्चा आगे आयेगी। (जारी) ❑

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

खतों से - पत्रों से

✱ अमरीका और कनाडा में **गुडईयर टायर एण्ड रबड़** कम्पनी की 16 फैक्ट्रियों में 12 हजार से ज्यादा मजदूरों ने 5 अक्टूबर से हड़ताल कर दी है। गुडईयर मैनेजमेन्ट नये भर्ती होने वाले मजदूरों को कम तनखा देने, पेन्शन में कटौती, चिकित्सा में कटौती, कार्यस्थल की स्थितियाँ बदतर करने और दो फैक्ट्रियाँ बन्द कर दो हजार मजदूरों की छँटनी के लिये यूनियन से सहमति बना चुकी है। चालीस प्रतिशत मजदूरों द्वारा मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौते को ठुकराने के बाद यूनियन ने हड़ताल की अनुमति दी। जिक्र कर दें, गुडईयर कम्पनी ने अपने मुख्य कार्याधिकारी को 2005 में 31 करोड़ 50 लाख रुपये (70 लाख डॉलर) दिये। [जानकारी "चैलेंज" अखबार से – CHALLENGE, P.O. 808 BROOKLYN, NY 11202, U.S.A.]

✱ शहर के चौराहों के बीच आग का ऐसा घर बना दिया जाये
गरीबों, बेसहारों और भिखारियों को जिसमें जिन्दा जला दिया जाये!
लिख दो इश्तहारों में और करा दो मुनादी के रोटी माँगना है गुनाह
जो कोई बोले उस पर बगावत का इल्जाम लगवा दिया जाये!

– इन्द्र "कुंवर कान्त", पिथौरागढ

✱ सरकार का दूसरा नाम "फरेब" है। .... हुकूमतें गाँवों, किसानों, मेहनतकशों को हर तरह से तबाह-बर्बाद करने पर तुली हैं। ... आबादी को जातिवाद-सम्प्रदायवाद में बाँटने से ले कर जमीन-जायदाद, घरबार से बेदखल करना इन हुकूमतों का मिशन बन गया है। ग्रामीण व व्यावसायिक बैंकों के दलाल, बड़े-छोटे वाहनों के डीलरों तथा ट्रैक्टर डीलरों के दलाल कमीशनखोरी के लालच में किसानों को फँसा कर बैंकों से कर्ज दिलवा कर वाहन अथवा ट्रैक्टर थमा देते हैं। फिर कर्ज पर ब्याज दर ब्याज बढता जाता है जिसे चुका पाना किसान के बूते के बाहर हो जाता है। तब जमीन-जायदाद, घर-द्वार सरकारों की नीलामी पर चढ जाते हैं। ... पुराने साहूकार यही सब करते थे, आज के नये साहूकार (बैंक) भी यही सब कर रहे हैं। .... – शिव दत्त, बाँदा

✱ यहाँ वहाँ हर जगह हम, जैसे होती घास
घास जैसी व्यथा कथा, रखते हैं हम पास।

– राधे लाल 'नवचक्र', भागलपुर

✱ .... इस युग के वैज्ञानिक विकास से आप कैसे लड़ेंगे। एक कम्प्युटर जिस दफ्तर में लग गया वहाँ पाँच काम करने वाले बेकार हो जाते हैं। भारत में सौ करोड़ से आगे बढता जनबल वैज्ञानिक प्रगति का तो शिकार होगा ही। ... – कमला प्रसाद 'बेखबर', फारबिसगंज

✱ ..... 'मसला यह व्यवस्था है' – निवेदन है कि मसला का समाधान यथास्थिति समाप्ति में है जो व्यवस्था परिवर्तन से ही सम्भव है जो तीसरी शक्ति यानि लोक शक्ति-जन शक्ति-ग्राम शक्ति यानि ग्राम स्वराज्य सभा-ग्राम सरकार, नगर स्वराज्य सभा-नगर सरकार के जागृत, संगठित एवं सक्रियता पर ही सम्भव है। ... – अनिरुद्ध कैलाश, गोड्डा

✱ जिसने एक क्षण भी
सुख से जिया
इसी धरा पर
स्वर्ग का आनन्द लिया। – नरेन्द्र नाथ, ग्वालियर

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी
फरीदाबाद–121001

✱ .... मजदूरों व आम लोगों की समस्यायें दिनोंदिन बढती ही जा रही हैं। .... कानून के हिमायती व बनाने वाले..... अपने स्वार्थ के लिये, अपनी ऐशो-आराम की दुनियाँ के लिये कितना गिर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। मजदूरों, गरीबों व लाचार लोगों के लिये आजादी का कोई अर्थ नहीं रह गया है। इनका हर पल गुलाम है, हर साँस बन्धक है। आसुरी साम्राज्य, आसुरी सत्ता के अधीन यह शोषित वर्ग जी रहा है यह अपने आप में दुनियाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य है। – बृजेन्द्र 'बैरागी', बलिया

✱ लगभग तीन वर्षों से किसानों पर टैक्सों की ज्यादती का सवाल उठा रहा हूँ। पूर्वज उपज का छठा भाग 'बलि' नाम से दान देते थे। सुल्तानों-शाहों को बढा कर पाँचवाँ हिस्सा 'फसलाना' नाम से बक्काल के जरिये दिया जाने लगा। चाणक्य-चन्द्रगुप्त मौर्य, फिरोज़ तुगलक और औरंगजेब के पूर्ववर्तियों ने वसूली बढाई थी। जन विद्रोह हुआ। उपर्युक्त ने निश्चित भाग पाना स्वीकार करके शान्ति कायम की। ..... कम्पनी सरकार ने टैक्स लगा कर वसूल किये। 1857 में गाँव-गाँव अवाम का उभार इसी वजह से था। इतिहासकारों ने इस कारण को छुपा दिया। 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के नेताओं ने भी टैक्स खत्म करने के मुद्दे को बेहद बल दिया था। ... सत्ता तो बदली...टैक्स और बढाये ही गये। .... – राजबल, मुजफ्फरनगर

✱ ... ऐसा पता चलता है कि औद्योगिक कानून अपनी जगह पर हैं और उद्योगपतियों के कानून अपनी जगह पर। कारखानों में श्रमिकों का कैसा शोषण होता है .... मजदूरों पर जो अत्याचार होते हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। .... – श्रवण कुमार, राँची

✱ ....आज आजादी के 59 साल बाद भी लगता है कि आम आदमी के कष्ट कम नहीं हुये। किसान आत्महत्या करने को विवश है, मजदूर दुर्दान्त यातनायें सह रहा है, न जीने योग्य हालातों में जी रहा है। तो, आजादी से हमें मिला क्या? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूँढना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। – रामसनेही 'यायावर', फिरोजाबाद

✱ .... स्वयं सहायता का भाव ही मूल बात है। ... यह दूसरी बात है कि जब सरकारी या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें ऐसे किसी सफल प्रयास को उठाती हैं और पूरे देश या विश्व में लागू करने का प्रयास करती हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। और जब उसका व्यावसायीकरण हो जाता है तब तो कहना ही क्या। .... सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारी जब सोचते हैं तो पूरे देश और दुनिया की सोचते हैं। उन्हें सदा अलाद्दीन के चिराग की तलाश रहती है जो एक झटके से समस्याओं को हल कर दे बगैर किसी विशेष प्रयास के। यही 'माइक्रोफाइनेन्स' के साथ हुआ है। वंचित तबके के साथ बगैर किसी विशेष सहानुभूति के सरकारी फरमान के तहत सरकारी कर्मचारी या एनजीओ के कर्मचारी 'समूह' बनाने में जुट गये, जबकि समूह बनाये नहीं जाते, समय के साथ विकसित होते हैं, अपना समय लेते हैं, परन्तु सरकारी या कारोबारी दुनिया में इतनी फुरसत कहाँ।

...."स्वयं सहायता समूह" के मौलिक रूप में काफी सम्भावनायें हैं। जहाँ एक तरफ सरकारी और मुनाफाखोर संस्थायें 'माइक्रोफाइनेन्स' को हर मर्ज का इलाज बताती हैं, वहीं इसके मौजूदा विकृत रूप को देख कर क्रान्तिकारी तबके इसे बिल्कुल नकार देते हैं।

... इस व्यवस्था में जो जितना अधिक गरीब होता है, उसे कर्ज उतनी ही ज्यादा मुश्किल, उतनी ही ज्यादा महंगी दर पर मिलता है। ....

'स्वयं सहायता' के एकमात्र सरकारी या व्यावसायिक विकृत रूप को देख कर, परिवर्तनकामी शक्तियों को ऐसे वास्तविक समूहों की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिये। परन्तु हो ऐसा ही रहा है। ...

.... सरकारी ठप्पे के चलते जनता के बीच से पनपी पहलकदमी को परित्यक्त करना उचित नहीं है। – राजेन्द्र, रोहतक का "अभियान" पत्रिका में पत्र [अभियान, पोस्ट बॉक्स–44, रोहतक (हरियाणा)]

✱ "आर्थिक आजादी आन्दोलन" (41, स्पोर्ट्स कॉलोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ– 250001 तथा बी-5/124 पश्चिम विहार, नई दिल्ली– 110063) के अनुसार मतदाताओं को केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं, सरकार से हर महीने नोट लेने का हक भी चाहिये। मतदाता को पहचान-पत्र की जगह रिजर्व बैंक का कार्ड दिया जाये जिस पर हर महीने 1750 रुपये मिलें। वैसे, पैसा बराबर-बराबर बाँटने पर 18 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक के हिस्से 3500 रुपये प्रतिमाह आते हैं। सरकार आधे को टैक्स के तौर पर रख ले और 1750 रुपये प्रत्येक मतदाता को हर महीने दे...'

✱ "अखिल भारत वैचारिक क्रान्ति मंच" (डी.एस-13 निराला नगर, लखनऊ – 226020) 25-26 नवम्बर को "वर्तमान विषम स्थिति व प्ररिस्थिति में तथा लोक कल्याण, व्यवस्था-परिवर्तन और राष्ट्र धर्म के परिप्रेक्ष्य में वैचारिक क्रान्ति की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवं उपादेयता" विषय पर परिचर्चा आयोजित कर रहा है। ❑

प्रिमियर आयरन वरकर : "प्लॉट 161 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 8 स्थाई मजदूर और 57 कैजुअल वरकर काम करते हैं। कैजुअल हैल्पर की तनखा 1700-1800 रुपये और ऑपरेटर की 2000 रुपये।" ❑

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून : ●37–40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7–10 तारीख तक दे ही देना; ●8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगुनी दर से; ● हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर-हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी और महीने में 4 छुट्टी पर जुलाई 06 से 2484 रुपये 28 पैसे है, 8 घण्टे काम के लिये 95 रुपये 55 पैसे; अर्धकुशल के 2594 रुपये 28 पैसे; कुशल के 2744 रुपये 28 पैसे; उच्च कुशल के 3044 रुपये 28 पैसे। जुलाई से डी.ए. के 36 रुपये 96 पैसे आये हैं।

दिल्ली फोरजिंग मजदूर : "प्लॉट 111 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में हम 150 वरकर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि सब की तनखा से काटी जाती हैं पर ई.एस.आई. कार्ड किसी मजदूर को नहीं दिया है। फैक्ट्री में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है और सुपरवाइजर गाली देते हैं। सितम्बर की तनखा आज 17 अक्टूबर तक नहीं दी है।"

सेक्युरिटी गार्ड : "3-बी मस्जिद मोड़, साउथ एक्स पार्ट II, नई दिल्ली में मुख्य कार्यालय वाली **सी.डी. सेक्युरिटी नेटवर्क लिमिटेड** दिल्ली, फरीदाबाद आदि में कम्पनियों को गार्ड, हैल्पर, सेल्समैन आदि प्रदत करती है। तनखा से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं पर वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. की पर्ची नहीं। गार्डों की आमतौर पर प्रतिदिन 12 घण्टे और महीने के तीसों दिन ड्युटी। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। बोनस नहीं देते, डी.ए. का एरियर भी नहीं देते।"

एस.पी.एल. इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 22 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने 10-15 ठेकेदारों के जरिये बड़ी सँख्या में मजदूर रखे हैं। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। तनखा में से काटा-पीटी की जाती है। पीस रेट के हिसाब से 150 रुपये बनते हैं तो 135-140 ही देते हैं। सिलाई विभाग के तीन ठेकेदार तो हम मजदूरों को बहुत-ही तंग करते हैं। सितम्बर की तनखा 18 अक्टूबर से देनी शुरू की है।"

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : "12/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 7 अक्टूबर को बॉयलर फटने से तीन वरकर जल गये थे — सप्ताह बाद अस्पताल में बॉयलर ऑपरेटर की मृत्यु हो गई। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। हैल्पर की तनखा 2000 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।

"इधर कम्पनी ने कहा है कि ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे नहीं कटवाओगे तो भगा देंगे। ई.एस.आई. कार्ड आसानी से तो देते ही नहीं और फिर ई.एस.आई. से इलाज करवाने का मतलब है दिहाड़ियाँ गँवाने के संग-संग लाइनों में लगने तथा डॉक्टरों-कर्मचारियों की बेरुखी वाले सिरदर्द मोल लेना। फण्ड में तो और भी ज्यादा परेशानी है — तनखा में से पैसे काट कर भविष्य निधि कार्यालय में जमा नहीं करना, नौकरी से निकाले जाने पर फण्ड के पैसे निकलवाने के वास्ते फार्म भरवाने के लिये फैक्ट्री के चक्कर काटना और फिर फण्ड दफ्तर के झमेले। **इधर कोई आदेश जारी कर स्वयं पी.एफ. संगठन ही थोड़े समय बाद नौकरी से निकाले जाते/निकाले दर्शाये जाते मजदूरों की भविष्य निधि राशि के एक हिस्से को हड़पने लगा है। ब्याज आधा प्रतिशत कम या ज्यादा की बातें अपनी जगह हैं, यहाँ तो पी.एफ. संगठन कैजुअल वरकरों तथा ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों की भविष्य निधि राशि के 35 प्रतिशत हिस्से को हड़प रहा है।** ऐसे में कुछ मजदूर भी ई.एस.आई. व पी.एफ. से बचने की कोशिश करते हैं।

"यूँ तो शिवालिक ग्लोबल फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की भरमार है परन्तु बुनाई विभाग में सब मजदूर कम्पनी स्वयं रखती है। हौजरी विभाग में 500 वरकर काम करते थे पर 15-20 दिन पहले 200 को भगा दिया, 5 सुपरवाइजर भी निकाल दिये। अन्य विभागों की ही तरह हौजरी में भी सुपरवाइजर गाली देते थे। हम मजदूरों ने आपस में तालमेल बढाये तो 2-3 महीने से साहबों ने गाली देनी बन्द कर दी हैं।

"फैक्ट्री में अब पीने का पानी ठीक है पर कैन्टीन में घटिया भोजन ही जारी है। सितम्बर की तनखा 18 अक्टूबर तक नहीं दी है।"

सनराइज कूलिंग सिस्टम वरकर : "प्लॉट 29 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से साँय 6½ तक और साँय 6½ से अगले रोज सुबह 6 या 8 बजे तक की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से और वह भी सिर्फ बेसिक के हिसाब से। रविवार को मैनेजमेन्ट जबरन काम करवाती है। रिजेक्शन पर अनुपस्थिति लगा देते हैं। छुट्टी करने पर तनखा रोक कर देते हैं। आधों की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। हैल्पर की तनखा 1800 रुपये और सफाई कर्मी की 1200 रुपये ही।"

श्याम अलॉयज वरकर : "प्लॉट 40 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 325 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. 35 के ही हैं। इधर 19 अक्टूबर को ग्राइन्डिंग व्हील टूटा और एक हैल्पर के पाँव को बुरी तरह काट दिया। कम्पनी ने एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरी और मैनेजिंग डायरेक्टर सत्य पाल घायल मजदूर का प्रायवेट इलाज कराने उसे एन एच 1 में डॉक्टर के पास ले गया।

"श्याम अलॉयज में 125 मजदूरों को ग्रुपों में बाँट कर 10 लोगों को ठेकेदार बना रखा है। भर्ती कम्पनी करती है, काम वो 10 लोग करवाते हैं। करीब 175 मजदूरों से कम्पनी स्वयं भी काम करवाती है। दोनों ही श्रेणी के मजदूरों को हैल्पर कहते हैं और दिवाली से पहले तक 8 घण्टे के 63 रुपये देते थे — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ओवर टाइम लगभग रोज ही 4 घण्टे का और इसके पैसे सिंगल रेट से।

"श्याम अलॉयज में दिवाली पर कम्पनी ने स्थाई मजदूर को 550 रुपये व मिठाई का डिब्बा, फाउन्ड्री में हैल्पर को 250 रुपये व मिठाई और मशीन शॉप में हैल्पर को 150 रुपये व मिठाई दी। दिवाली बाद, 24 अक्टूबर को मशीन शॉप में हैल्परों ने 11 बजे काम बन्द कर दिया। भोजन अवकाश के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर सत्य पाल मशीन शॉप हैल्परों से मिला तथा कहा कि दिवाली के 100 रुपये और दे देंगे। दिहाड़ी कम से कम 90 रुपये करने की बात पर मैनेजिंग डायरेक्टर सत्य पाल ने कहा कि इसे 63 से बढा कर 65 रुपये कर देंगे पर इससे ज्यादा नहीं....

"श्याम अलॉयज में बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इससे थोड़ी राहत देने वाला एग्जॉस्ट फैन 6 महीने से खराब पड़ा है।"

ए. पी. फोरजिंग मजदूर : "16/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 2100 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। मैनेजर गाली देता है। हम मजदूरों की सितम्बर माह की तनखा में से कम्पनी ने 200-250 रुपये काट लिये और फिर दीवाली उपहार बतौर 250-300 रुपये दिये।" **(बाकी पेज दो पर)**

दिल्ली से..... **(पेज चार का शेष)**

दिल्ली में होता हूँ तो जब काम आ गया जाना पड़ता है और बाहर होता हूँ तो चौबीसों घण्टे की ड्युटी होती है। रविवार, ओवर टाइम, बोनस, ई.एस.आई., पी.एफ. आदि में कुछ भी नहीं होता... अक्सर अनुमति-पत्र पर ड्राइवर के हस्ताक्षर तक नहीं होते। आठ घण्टे की नहीं बल्कि एक दिन की दिहाड़ी 200 रुपये। एक दिन में औसतन 300 किलो मीटर गाड़ी चलानी पड़ती है पर लाइन के ड्राइवरों को 500 का एवरेज देना पड़ता है। यह औसत 9 से 60 टन वजन, बॉर्डर, पुलिस, टोल टैक्स, आर टी ओ, दादा लोग, बैरियर, पुल, रेल फाटक, घाट, शहर, मरम्मत के संग। तनाव और प्रदूषण के कारण ड्राइवर सर्दी-जुकाम, कमर दर्द, कब्ज, पेशाब में दिक्कत, पैरों में दर्द, ... और एक्सीडेन्ट के शिकार होते हैं। सामान लादने-उतारने, रस्सा-तिरपाल, गाड़ी की सफाई, हिसाब-किताब...और एवरेज के चक्कर में ड्राइवरों को नहाने-खाने-सोने के लिये समय नहीं मिलता। काम के हालात ही ऐसे हैं कि ड्राइवर गन्दे-भद्दे दिखते हैं। नशा किये बिना ड्राइवरी करना बहुत मुश्किल है। नियम-कानून तोड़े बिना टारगेट पूरे हो ही नहीं सकते - इसलिये ट्रान्सपोर्ट कम्पनियाँ ड्राइवरों को "खर्चा" देती हैं और थाणेदार-हवलदार-आरटीओ की फौज इस "खर्चे" में हिस्सा-पत्ती के लिये तैनात है। **इस सब के दौरान बदतमीजी झेलना और बदतमीजी करना ड्राइवरों की नियति-सी बन गई है।**"❑

बन्दी वाणी (11)

अमरीका सरकार ने "अपने" बीस लाख लोगों को सज़ा दे कर और आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना रखा है। यूँ तो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में ढाल दिया गया है, अधिकाधिक ढाला जा रहा है, फिर भी, सरकारों के कारागारों में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकड़ हम से अधिक होती है। अमरीका में कैलिफोर्निया प्रान्त की एक जेल में बन्द गैरी हॉलफोर्ड के और पत्र इधर हमें मिले हैं।

इस दौरान पहेली की कुछ और कड़ियाँ जुड़ गई हैं इसलिये सरकार अधिकाधिक मूर्ख दिख रही है। अमरीका सरकार अन्य सरकारों को "मानव अधिकारों" पर प्रवचन देती रहती है पर अमरीका में स्वयं अमरीका सरकार मानव अधिकारों के हनन पर मौन सहमति देती है।

मेरे द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद यह अधिकाधिक स्पष्ट हो गया है कि "सत्ता प्रतिष्ठान" के अन्दर कोई भी अपने स्वयं के जीवनयापन के अलावा किसी भी चीज के बारे में फिक्र नहीं करता- करती। आने वाली पीढियों को जो नुक्सान ये लोग कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है... कम्पनियों का मुनाफा एकमात्र "नैतिक दिशासूचक" है इनके लिये। एक मानव के तौर पर यह प्रवृति मुझे लज्जित करती है...

अमरीका में निवास में एक बड़ी भारी दिक्कत राजनीतिक चिन्तन में ध्रुवीकरण तथा एक अक्षम अथवा अप्रभावी लगती प्रेस है। टी वी, रेडियो, पत्र-पत्रिकायें उन राजनीतिक सूत्रों का अनुसरण करते हैं जो चन्द लोगों का ही समर्थन करते हैं। जिनका समर्थन किया जाता है वे आमतौर पर अमीर व शक्तिशाली होते हैं और समाधान की बजाय स्वयं समस्या होते हैं। किसी निर्वाचन का कोई मुद्दा हो जो एक उद्योग से जुड़ा हो, अथवा सम्पूर्ण मानवता को प्रभावित करती कोई आपदा हो, जो विवरण दिये जाते हैं वो वास्तविकता से इतने भिन्न होते हैं कि समाचारों में कोई नैतिकता बची नहीं लगती।

अमरीका में अधिकतर लोगों की इच्छा रहती है कि जिन अत्याचारों के बारे में वे जानते हैं उन्हें अनदेखा करें, उनके खिलाफ बोलें नहीं। जब तक उनके पास निवास के लिये स्थान है, चलाने को कार है, खाने के लिये भोजन, और खेलने को "खिलौने", तब तक उनकी अत्याचार का विरोध करने और अल्पसँख्याँ की रक्षा करने की इच्छा नहीं होती....समस्या यह है कि समय के भिन्न-भिन्न चरण में हर कोई अल्पसँख्या में आ जाता - जाती है.... Gary Hallford, T-58516, C.S.P.-Solano, 17-211L, P.O. Box 4000, Vacaville, CA 95696-4000, U.S.A.

दिल्ली से -

कक्षा दो का छात्र : "मैं 8 साल का हूँ और कक्षा दो में पढता हूँ। सुबह 7 बजे उठता हूँ, लैट्रिन जाता हूँ, ब्रुश करता हूँ, नहाता हूँ पर कभी - कभी यूँ ही नहाने का दिल नहीं करता तो नाश्ता कर लेता हूँ। न नहाने पर मम्मी - पापा डाँटते हैं। आठ बजे स्कूल जाता हूँ। प्रार्थना, नाखुन, बाल, ड्रेस, होम वर्क.... किसी न किसी में पिटाई निश्चित है। स्कूल जाना अच्छा लगता है पर पढना अच्छा नहीं लगता। खेलने का आधा घण्टा और लन्च का आधा घण्टा बहुत अच्छे लगते हैं। छुट्टी 12½ बजे होती है और धीरे - धीरे वापस आता हूँ। कमरे पर कोई नहीं होता क्योंकि मम्मी - पापा कम्पनियों में काम करते हैं। मम्मी सुबह 9 बजे जाती है और रात को 9 बजे आती है। पापा सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं। स्कूल से आने के बाद 7 बजे तक अकेला रहता हूँ। रविवार को भी अकेला रहता हूँ क्योंकि मम्मी उस दिन भी ड्युटी जाती हैं और पापा कहीं चले जाते हैं या मैच देखते हैं। स्कूल से एक बजे कमरे पर पहुँच कर हाथ - मुँह धो कर खाना खाता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ। फिर कमरे के ताला लगा कर ऊपर रह रही आँटी के पास टी.वी. देखने चला जाता हूँ। चार बजे ट्युशन जाता हूँ और 5½ लौटता हूँ। फिर 6½ - 7 तक दोस्तों के साथ छत पर खेलता हूँ। पापा 7 बजे ड्युटी से आते हैं और हाथ - मुँह धो कर खाना बनाने लगते हैं। तब मैं होम वर्क करता हूँ। कभी - कभी पापा प्रश्न पूछते हैं और उत्तर नहीं आने पर मारते हैं लेकिन पढाते नहीं। खाना बनने में 9 बज जाते हैं तब मम्मी आती है। मैं 9½ बजे सो जाता हूँ।"

लिलिपुट इन्टरनेशनल मजदूर : "डी - 3 ओखला फेज1 स्थित कम्पनी में हम 60 महिला व पुरुष वरकर हैं। डी - 3 में ही स्थित आनन्द इन्टरनेशनल फैक्ट्री में हम 10 साल से काम कर रहे थे। पिछले महीने से फाइलों में हम नये मजदूर हैं। फाइलों में ही हमें आनन्द इन्टरनेशनल से निकाल कर लिलिपुट इन्टरनेशनल में कर नई भर्ती दिखाई गई है। हमें 12 घण्टे रोज ड्युटी पर महीने के 3271 रुपये देते हैं — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। पैसे अगले महीने की 12 तारीख से पहले नहीं देते।"

ट्रक ड्राइवर : "मैं अपनी दाल - रोटी के लिये गाड़ी चलाता हूँ। ट्रक चलाने का न तो मेरा शौक है और न ही ऐसा करने की मेरी इच्छा। ट्रक ड्राइवर होना मेरी मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी। हमारा कोई ड्युटी टाइम नहीं होता। **(बाकी पेज तीन पर)**

विचारणीय

पेन्ट से सावधान

एक मित्र 15 वर्षों से इंग्लैण्ड में इमारतों में सीमेंट, स्टील और पेन्ट के प्रयोग के खिलाफ अभियान में शरीक हैं। वह निर्माण कार्यों में प्रकृति द्वारा उपलब्ध सामग्री को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्र के अनुसार इंग्लैण्ड में साठ प्रतिशत लोगों को साँस की तकलीफें हैं और इनका एक बड़ा कारण निवास व कार्यस्थलों में सीमेन्ट- लोहे- पेन्ट का प्रयोग है। समस्या की भयावहता के कारण मित्र और उनके साथियों की बातें इंग्लैण्ड में सुनी जाने लगी हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत सामग्री से भवन निर्माण करना तथा रंग बनाना स्वास्थ्य के माफिक हैं। मित्र के अनुसार मकान साँस लेते हैं! सीमेन्ट- स्टील- पेन्ट का विरोध और निवास तथा कार्यस्थल को स्वास्थ्य के अनुरूप बनाने का अभियान यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी चल रहा है।

इधर जर्मनी से एक मित्र ने इन्टरनेट पर उपलब्ध कुछ जानकारी भेजी है। अमरीका में 31 वर्ष तक पेन्टर का कार्य करने वाले मजदूर रोलैंड शेप्पर्ड को कैन्सर हो गया। कार्यस्थितियों के कारण कैन्सर हुआ है का आंकलन कर रोलैंड ने क्षतिपूर्ति के लिये अमरीका में न्यायालय में 5 वर्ष मुकदमा लड़ा और तीन लाख डॉलर (एक करोड़ 35 लाख रुपये) का हर्जाना वसूल किया। अपने अनुभवों और अध्ययनों के आधार पर रौलैंड बताते हैं :

— पेन्ट करने वाले वरकर का प्रतिदिन 150 कैन्सर पैदा करने वाले और 3000 अन्य खतरनाक पदार्थों से वास्ता पड़ता है। सरकारें और उनकी संस्थायें मजदूर की 100 प्रतिशत सुरक्षा के पैमाने निर्धारित ही नहीं करती। कार्यस्थलों पर मजदूरों का घायल होना, मरना कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अमरीका सरकार के विशेषज्ञों के अनुसार बाकी आबादी की तुलना में मजदूरों में प्रति हजार पर एक अधिक के कैन्सर होना आर्थिक तौर पर स्वीकार्य है। और, कार्यस्थलों पर सुरक्षा का पैमाना निर्धारित करने वाली सरकारी संस्था सरकारी विशेषज्ञों के मानक से दस से 50 गुणा अधिक की छूट कम्पनियों को प्रदान करती है — बेन्जीन एक करोड़ कणों में एक कण की जगह दस कण का पैमाना। और, ऐसे जो पैमाने बनाये जाते हैं उन पर भी अमल कितना होता है? स्टाफ की कमी, साधनों की कमी, भ्रष्टाचार का बोलबाला संसार- भर में सरकारों के श्रम विभागों/कारखाना सुरक्षा विभागों में आम बात है।

— पेन्ट में बेन्जीन, इथिलीन ऑक्साइड, फॉरमैल्डिहाइड, इथिलीन ग्लाइकोल कैन्सर पैदा करने वाले मुख्य तत्वों में हैं। अधिकतर लेटैक्स पेन्टों का प्रमुख अंश इथिलीन ग्लाइकोल होता है और यह रेडियेटर में डाला जाता तरल भी होता है। इथिलीन ग्लाइकोल को चमड़ी व आँख के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिये और मजदूर को रोज कपड़े बदलने चाहियें।

— सरकारें इस बात की गारन्टी करती हैं कि पेन्ट करने वाले मजदूरों को कैन्सर एक बड़ा खतरा बना रहे। पेन्ट वरकरों की पत्नियों व बच्चों में भी कैन्सर की ऊँची दर है। बचाव के लिये मजदूरों को स्वयं पहलकदमी करनी होगी। पेन्ट करते समय साँस लेने का उपकरण पहनना भारत में अभी शायद बड़ी बात लगे पर दस्ताने, चश्मे और पूरी बाजू की कमीज तो मजदूरों को पहनने ही चाहियें।

जिक्र कर दें कि एक अनुसन्धानकर्ता छात्र के अनुसार **कार्यस्थलों की हालात के कारण** 2005 **में दुनियाँ में 8 लाख मजदूरों की मृत्यु हुई और दस करोड़ मजदूरों के गम्भीर चोटें लगी। हर पल हर क्षेत्र में कार्यस्थल भयावह मारकाट वाले युद्ध क्षेत्र हैं।** ☐

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73